गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सिक्योरिटी आधारित 5100 करोड़ का ऋण

सीएम व केंद्रीय वित्त मंत्री की मौजूदगी में पीएनबी के एमडी ने सौंपा ऋण स्वीकृति पत्र

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने लिए बैंकों से 'सिक्योरिटी' आधारित ऋ ण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। इसके तहत यूपीडा ने पंजाब नेशनल बैंक से 5100 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी प्राप्त की। शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में पीएनबी के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एसएस मल्लिकार्जुन ने शासन को ऋण स्वीकृति पत्र हस्तांतरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं।

सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों के मुद्रीकरण का यह न सिर्फ प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में पहला प्रयास है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों को जुटाने में मुद्रीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का केंद्र रहा है, बल्कि अब देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन भी बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ साबित होगा।

देश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के जरिए गोरखपुर क्षेत्र को बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जा रहा है। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 594 किमी होगी और निर्माण में 36,230 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा। ब्यूरो